

खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग की योजनाओं का लाभ पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ पात्र लाभार्थियों तक पहुँचना सुनिश्चित किया जाए—श्री मनोज कुमार पाण्डेय

विभागीय योजनाओं की प्रगति, लंबित प्रकरणों एवं शासन स्तर पर दिए गए निर्देशों की हुई विस्तृत समीक्षा

विधानसभा एवं विधान परिषद से संबंधित सूचनाओं के समयबद्ध निस्तारण तथा स्थायी समितियों के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर

विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, जवाबदेह एवं जनहितकारी बनाने पर विशेष बल

लखनऊ : 09 अक्टूबर, 2026

उत्तर प्रदेश के माननीय खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी की अध्यक्षता में आज विभागीय योजनाओं एवं विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग द्वारा संचालित एवं प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति, शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों, जनप्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं तथा पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनहितकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पारदर्शी, सुगम एवं समयबद्ध ढंग से पहुँचाना है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की कि सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, जवाबदेही तथा निर्धारित समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाए।

बैठक के दौरान वर्तमान में संचालित एवं प्रस्तावित विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए विभागीय स्तर पर नियमित अनुश्रवण एवं आपसी समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।

माननीय मंत्री जी ने विधानसभा एवं विधान परिषद के विभिन्न नियमों के अंतर्गत माँगी गई सूचनाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विषयों का गंभीरता से संज्ञान लिया जाना चाहिए। संबंधित सूचनाएँ तथ्यपरक, स्पष्ट एवं निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराई जाएँ, जिससे सदन की कार्यवाही एवं संसदीय प्रक्रियाओं के प्रति विभागीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने स्थायी समितियों की बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए कहा कि समितियों की संस्तुतियों एवं निर्णयों पर नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही पूर्व में दिए गए विभिन्न निर्देशों तथा लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए।

बैठक में विभाग के अधीन निगमों एवं परिषदों की समितियों के गठन के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि विभागीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।

खाद्यान्न वितरण व्यवस्था के अंतर्गत नमक को सम्मिलित किए जाने के विषय पर भी बैठक में विचार-विमर्श किया गया। माननीय मंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में आवश्यक तथ्यों, व्यावहारिक पहलुओं एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार परीक्षण किए जाने की अपेक्षा की।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि खाद्य एवं रसद विभाग सीधे आमजन की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ विभाग है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी का दायित्व है कि वह संवेदनशीलता, सकारात्मक सोच एवं सेवाभाव के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे। विभागीय व्यवस्थाओं को निरंतर बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, पारदर्शिता एवं प्रभावी निगरानी व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप विभागीय योजनाओं का संचालन इस प्रकार किया जाए कि आमजन को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े तथा शासन की जनकल्याणकारी नीतियों का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुँच सके।

बैठक में प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, श्री अनिल कुमार; अपर आयुक्त (खाद्य एवं रसद) श्री कामता प्रसाद; अपर आयुक्त श्री सत्यदेव तथा शासन एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सम्पर्क सूत्र— अखिलेश पाण्डेय

राघवेन्द्र / 04:05 PM

फोन नम्बर Direct : 0522-2239023 ईपीओ/एक्सओ : 0522-2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225

फैक्स नं० : 0522-2237230 0522-2239586 ई-मेल : upssochna@gmail.com,

वेबसाइट : www.information.up.gov.in